भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †5304

उत्तर देने की तारीख- 03/04/2025

आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पीएम-जनमन योजना

†5304.श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

श्री कालिपद सरेन खेरवाल:

श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जनमन योजना की प्रगति और कार्यान्वयन के संबंध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण या अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत देश भर में घटकवार और राज्यवार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में प्रकाशम और एलुरू जिलों सहित जिलावार प्रस्तावित, अनुमोदित और वर्तमान में लागू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में आबंटित, जारी की गई और उपयोग की गई कुल निधि का राज्यवार, विशेषकर प्रकाशम और एलुरू जिलों सहित आन्ध्र प्रदेश में जिलावार ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में उक्त योजना से लाभान्वित युवाओं और महिलाओं सहित लाभार्थियों की कुल संख्या का घटकवार और राज्यवार, विशेषकर प्रकाशम और एलुरू जिलों सहित आन्ध्र प्रदेश में जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त योजना और इसके अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई अभियान चलाया है और यदि हां, तो विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जनमन योजना कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(छ) उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और पश्चिम बंगाल में लाभार्थियों की अनुमानित संख्या कितनी है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (घ): 15 नवंबर 2023 को, माननीय प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) का शुभारंभ किया। पीएम जनमन को 16 महीने से क्रियान्वित किया जा रहा है और पीएम जनमन की प्रगति और कार्यान्वयन के संबंध में कोई हालिया सर्वेक्षण या अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन/विभागों के माध्यम से पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पीएम जनमन के तहत कवर किए गए गांवों और बस्तियों में रहने वाली

पीवीटीजी आबादी को कवर करने के लिए पीवीटीजी आबादी के आंकड़ों और बुनियादी ढांचे के अंतरों का अनुमान लगाने के लिए आवास स्तर पर डेटा संग्रह कार्य शुरू किया है। एकत्र किए गए डेटा (28.02.2025 तक) के आधार पर, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार, पीवीटीजी आबादी को **अनुलग्नक-I** में सारणीबद्ध किया गया है। तथापि, इन अभियानों के अंतर्गत कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की वास्तविक संख्या अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संबंधित उपायों के विशिष्ट दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अधीन है।

(ख) और (ग): प्रधानमंत्री जनमन के उद्देश्यों को 9-लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। योजना के तहत लक्षित परियोजनाओं/उपायों का विवरण **अनुलग्नक II** में दिया गया है। अभियान के तहत परियोजनाओं की प्रगति का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है और अभियान के तहत प्रकाशम और एलुरु जिलों सहित आंध्र प्रदेश में जिले-वार प्रगति **अनुलग्नक-IV** में दी गई है। वित्तीय स्वीकृतियों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-V** में दिया गया है।

(ङ): आंध्र प्रदेश सहित राज्य सरकारों के समन्वय से आईईसी शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन धन बैंक खाता जैसे बुनियादी दस्तावेजों को तैयार करने में सुविधा प्रदान करना है, जो आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास, मनरेगा आदि सहित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

(च) और (छ): लाइन मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य में आवास (पीएमएवाई-जी), सड़कों (पीएमजीएसवाई), आंगनवाड़ी और छात्रावासों (समग्र शिक्षा) के उपाय के संबंध में अभियान के तहत कोई प्रगति नहीं देखी गई है। मिशन को तीन वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय नियमित रूप से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत गतिविधियों (जनजातीय कार्य मंत्रालय के उपायों सहित) के कार्यान्वयन का मुद्दा उठाता रहा है। एकत्र किए गए आंकड़ों (अक्टूबर 2024 में अद्यतन) के आधार पर, पश्चिम बंगाल राज्य में पीवीटीजी जनसंख्या 67431 है।

अनुलग्नक-I

"आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पीएम-जनमन योजना" के संबंध में श्री मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, श्री कालीपद सरेन खेरवाल एवं श्री पुट्टा महेश कुमार द्वारा उठाए गए दिनांक 03.04.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †5304 के भाग (क) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों / विभागों द्वारा मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित आवास सर्वेक्षण के आधार पर पीवीटीजी जनसंख्या का अनुमान (28.02.2025 तक)

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**कुल पीवीटीजी जनसंख्या**
1	आंध्र प्रदेश	493932
2	छत्तीसगढ़	229743
3	गुजरात	153516
4	झारखंड	398260
5	कर्नाटक	57067
6	केरल	29511
7	मध्य प्रदेश	1228606
8	महाराष्ट्र	621046
9	ओडिशा	298441
10	राजस्थान	128456
11	तमिलनाडु	364846
12	तेलंगाना	63194
13	त्रिपुरा	273240
14	उत्तर प्रदेश	3527
15	उत्तराखंड	92233
16	पश्चिम बंगाल	67431
17	अंडमान और निकोबार	191
18	मणिपुर	44694
19	बिहार	8839
कुल योग		**4556773**

अनुलग्नक-II

"आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पीएम-जनमन योजना" के संबंध में श्री मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, श्री कालीपद सरेन खेरवाल एवं श्री पुट्टा महेश कुमार द्वारा उठाए गए दिनांक 03.04.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †5304 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएम जनमन के अंतर्गत लक्षित परियोजनाओं/उपायों का विवरण

मंत्रालय का नाम	**गतिविधि**	**मिशन लक्ष्य (2023-2026)**
ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के मकानों का प्रावधान	4.90 लाख मकान
	संपर्क मार्ग	8000 किमी सड़क
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सचल चिकित्सा इकाइयाँ	1000 एमएमयू (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार सभी को कवर करने के लिए 725 एमएमयू पर्याप्त हैं)
जल शक्ति मंत्रालय	पाइप से जल आपूर्ति	18810 गांव
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण एवं संचालन	2500
शिक्षा मंत्रालय	छात्रावासों का निर्माण और संचालन	500
संचार मंत्रालय	मोबाइल टावरों की स्थापना	4543 बस्तियों को कवर किया गया
विद्युत मंत्रालय	अविद्युतीकृत आवासों का ऊर्जाकरण	142133 आवास
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	नई सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत स्वीकृत घर	सभी पात्र और एमओपी द्वारा कवर नहीं किए गए
जनजातीय कार्य मंत्रालय	बहुउद्देशीय केंद्र	1000
	वीडीवीके की स्थापना	500

अनुलग्नक-III

"आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पीएम-जनमन योजना" के संबंध में श्री मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, श्री कालीपद सरेन खेरवाल एवं श्री पुट्टा महेश कुमार द्वारा उठाए गए दिनांक 03.04.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †5304 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएम जनमन के अंतर्गत स्वीकृत एवं क्रियान्वित परियोजनाओं की प्रगति का विवरण (31.03.2025 तक)

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमएवाई-जी)	ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजीएसवाई)	एमओजेएस (जेजेएम)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनआरएचएम)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पोषण 2.0)	शिक्षा मंत्रालय (एसएसए)	एमओपी (आरडीएसएस)	एमएनआरई	एमओसी (डीओटी-यूएसओएफ)	जनजातीय कार्य मंत्रालय	
		स्वीकृत मकान	स्वीकृत सड़कें (कि.मी. में)	स्वीकृत गांव	स्वीकृत एवं संचालित एमएमयू	स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र	स्वीकृत छात्रावासों की संख्या	स्वीकृत आवास	स्वीकृत आवास	कवरेज के लिए नियोजित बस्ती (सं.)	स्वीकृत एमपीसी (संख्या)	स्वीकृत वन धन विकास केंद्र (संख्या)
1	आंध्र प्रदेश	41935	612.718	1859	141	266	8	25054	1675	1545	125	73
2	छत्तीसगढ़	27577	2449.108	1407	58	174	31	7077	1578	187	75	16
3	गुजरात	10871	1.55	572	17	67	5	6626	0	48	39	21
4	झारखंड	34637	126.05	2502	55	386	10	12442	2342	519	113	35
5	कर्नाटक	1100	63.756	439	5	22	1	1615	179	36	74	33
6	केरल	661	0	96	24	7	4	345	98	52	15	7
7	मध्य प्रदेश	172045	1835	4519	74	572	51	29290	2060	203	125	83
8	महाराष्ट्र	43538	50.14	2520	84	145	13	8556	0	317	121	40
9	ओडिशा	35750	147.87	1103	50	90	30	2866	0	443	74	43
10	राजस्थान	21029	98.687	337	6	51	4	17633	0	4	18	50
11	तमिलनाडु	9004	0	1370	105	34	8	10673	0	158	60	37
12	तेलंगाना	0	66.98	300	22	85	8	3884	326	97	73	25
13	त्रिपुरा	17241	203.11	251	6	141	14	11664	1703	57	50	30
14	उत्तर प्रदेश	145	0	7	2	1	2	316	0	5	5	5
15	उत्तराखंड	1941	0	115	24	7	3	669	0	1	15	5
16	पश्चिम बंगाल	0	0	414	14	0	0	3372	0	6	0	0
17	अंडमान और निकोबार	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1
18	मणिपुर	1711	0	27	0	42	2	0	0	0	11	2
19	बिहार	0	0	33	0	49	0	51	0	0	7	0
कुल योग		**419185**	**5655.0**	**17873**	**687**	**2139**	**194**	**142133**	**9961**	**3679**	**1000**	**506**

अनुलग्नक-IV

"आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पीएम-जनमन योजना" के संबंध में श्री मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, श्री कालीपद सरेन खेरवाल एवं श्री पुट्टा महेश कुमार द्वारा उठाए गए दिनांक 03.04.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †5304 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएम जनमन के अंतर्गत प्रकाशम और एलुरु जिलों सहित आंध्र प्रदेश में जिले-वार प्रगति (31.03.2025 तक)

क्र. सं.	जिलों के नाम	स्वीकृत मकान	स्वीकृत सड़कें (किमी में)	पाइप जलापूर्ति के लिए स्वीकृत गांवों की संख्या	स्वीकृत और संचालित एमएमयू की संख्या	स्वीकृत छात्रावासों की संख्या	स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	कवरेज के लिए स्वीकृत पीवीटीजी बस्तियों की संख्या	विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत आवास	नई सौर ऊर्जा योजना के तहत स्वीकृत पीवीटीजी आवासों की संख्या	स्वीकृत एमपीसी की संख्या	स्वीकृत वन धन विकास केंद्र की संख्या
1	अल्लूरी सीताराम राजू	32185	483.64	1156	35	0	200	959	17363	728	66	16
2	अनकापल्ली	0	0	48	11	0	0	12	29	0	0	0
3	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनसीमा	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
4	पूर्वी गोदावरी	0	0	6	6	0	0	0	4	0	0	0
5	एलुरु	558	34.87	43	4	0	0	47	1186	305	16	4
6	काकीनाडा	0	19.15	9	3	0	0	15	0	0	0	0
7	नांदयाल	527	7.11	31	13	3	0	4	213	0	0	0
8	एनटीआर	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0
9	पलनाडु	600	0	29	6	0	0	4	480	0	0	0
10	पार्वतीपुरम मान्यम	5447	38.65	263	26	2	29	325	3392	28	26	15
11	प्रकाशम	686	0	31	8	0	1	19	982	611	2	0
12	श्रीकाकुलम	1742	13.7	196	22	3	35	152	879	0	15	38
13	विजयनगरम	190	15.6	31	4	0	1	8	119	0	0	0

अनुलग्नक-V

"आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पीएम-जनमन योजना" के संबंध में श्री मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, श्री कालीपद सरेन खेरवाल एवं श्री पुट्टा महेश कुमार द्वारा उठाए गए दिनांक 03.04.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †5304 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

जनजातीय कार्य मंत्रालय के उपायों के लिए पीएम-जनमन के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निधियों की स्वीकृति/निर्मुक्ति*

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**जनजातीय कार्य मंत्रालय**	
		एमपीसी	**वीडीवीके**
1	आंध्र प्रदेश	19.97	3.105
2	छत्तीसगढ़	8.52	1.1976
3	गुजरात	6.03	0.525
4	झारखंड	2.12	1.438
5	कर्नाटक	13.59	0.892
6	केरल	2.29	0.2166
7	मध्य प्रदेश	25.99	2.5755
8	महाराष्ट्र	17.47	1.812
9	ओडिशा	36.60	1.7765
10	राजस्थान	6.76	4.3296
11	तमिलनाडु	25.87	1.2015
12	तेलंगाना	16.16	0.7305
13	त्रिपुरा	12.07	1.27
14	उत्तर प्रदेश	0.83	0.1595
15	उत्तराखंड	5.40	0.157
16	पश्चिम बंगाल	0.00	0
17	अंडमान और निकोबार	0.00	0.028
18	मणिपुर	0.00	0
19	बिहार	0.00	0
कुल योग		**199.68**	**21.41**

** मंत्रालय में जिला-वार आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

* जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जाने वाले उपायों के लिए उपयोग की गई धनराशि का रिकॉर्ड नहीं रखता है।

*****